भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2583

जिसका उत्तर मंगलवार, 09 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

विद्युत उपकरण उद्योग

2583. श्रीमती संतोष अहलावत:

श्री नलीन कुमार कटील:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उपकरण उद्योग की खराब स्थिति पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग अभियान योजना को शुरू करने सहित इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभियान के अंतर्गत क्या उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां।

(ख): घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्माण उद्योग ने विगत वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र की मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता स्थापित कर ली है। तथापि, निम्नलिखित कारकों की वजह से घरेलू विद्युत उपकरण विनिर्माण उद्योग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है:

- कोयला/ईंधन लिंकेज, भूमि, पर्यावरणीय मंजूरी आदि से संबंधित मुद्दे/अवरोध जिनके परिणामस्वरूप घरेलू बाजार में आर्डरों में तेजी से गिरावट।
- आर्डरों का आस्थगित होना अथवा उन्हें रोक लिया जाना।
- कमजोर निवेश वातावरण तथा ऋणप्रदाता संस्थाओं की तरफ से वित्त देने में अड़चनें।
- भुगतान करने में उपभोक्ताओं की मजबूरियां जिनसे कुछ विद्युत परियोजनाओं की प्रगति में रुकावट।

- सुपर-क्रिटिकल बॉयलरों और टरबाइन जनरेटरों के लिए देश में निजी क्षेत्र में नई कंपनियों की संख्या बढ़ जाने/संयुक्त उद्यम बन जाने के कारण प्रतियोगिता बढ़ी जिसके फलस्वरूप मूल्य प्राप्ति प्रभावित हुई तथा लाभ पर असर पड़ा।
- विदेशी पूर्तिकारों/विनिर्माणकर्ताओं की तुलना में घरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जा रहे अवसंरचना संबंधी कमियों सहित समान अवसर की कमी।
- वैश्विक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप निर्यात के लिए कम मांग।
- महत्वपूर्ण आवकों/कच्चे माल की घरेलू स्तर पर उपलब्धता की कमी।
- जनशक्ति का अभाव।

उपर्युक्त कारकों की वजह से, स्वदेशी तैयार विनिर्माणकारी क्षमताओं का वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है।

(ग): जी, हां।

(घ): घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग के विकास और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए, भारत सरकार ने 24.07.2013 को इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री मिशन प्लान 2012-22 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उद्योग की वृद्धि को गतिशील और धारणीय बनाने के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों को दिशा देना, उनमें समन्वय तथा तालमेल कायम करना है। मिशन प्लान में व्यक्त विजन 2022 के अंतर्गत विद्युत उपकरण के उत्पादन में भारत को पसंदीदा देश बनाना तथा निर्यात और आयात में संतुलन कायम करते हुए 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का आउटपुट हासिल करना है। मिशन प्लान में कार्यनीतिक और नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए सरकार और उद्योग, दोनों के द्वारा पांच क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं। ये हैं (i) उद्योग प्रतिस्पर्धात्मकता, (ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन, (iii) कौशल विकास, (iv) निर्यात, और (v) अंतर्निहित मांग का परिवर्तन।

इन सभी पांच प्रमुख क्षेत्रों में, इस मिशन प्लान में सरकार और उद्योग सहित अलग-अलग हितधारकों द्वारा कार्यनीतिक और नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए विस्तृत सिफारिशों के साथ-साथ घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग की वर्तमान स्थिति/सरोकार के क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं।

******